RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : गुरुवार 18 मई 2023 वर्ष 05 अंक 30 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 8 कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

14 साल बाद डकैती का आरोपी गिरफ्तार

पालघर : महाराष्ट्र के पालघर में डकैती के मामले में 14 साल से अधिक समय से फरार आरोपी को पुलिस ने सतारा जिले से गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मीरा भायंदर-वसई विरार पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक राहुल राख ने कहा कि 21 अगस्त, 2008 को कुछ लोग विरार इलाके में एक मकान में घुसे और वहां रहने वाले लोगों को लोहे की छड़ों से पीटने के साथ ही 17,000 रुपये मूल्य के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि आरोपियों में से एक की पहचान तेचर बंद्या काले के रूप में हुई। पुलिस ने इसके बाद इस संबंध में डकैती का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। बाद में इसमें काले तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्त महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के प्रावधान भी जोड़े गए। पुलिस को यह पता चला कि काले डकैती के कई अन्य मामलों में भी शामिल है और वह गिरफ्तारी से बच रहा है।

लगातार बारिश प्राकृतिक आपदा घोषित...

भवन पुनर्विकास नीति

कैबिनेट बैठक का फैसला

मुंबई : मुंबई में आज राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. लगातार बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहत एवं पुनर्वास विभाग को पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

भवन पुनर्विकास नीति

पिछड़ा वर्ग सहकारी आवास योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए भवनों के पुनर्विकास नीति की घोषणा करने का निर्णय आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। पिछड़ा वर्ग सहकारी आवास समितियों के भवनों का निर्माण हुए लगभग 55 से 60 वर्ष बीत चुके हैं। अधिकांश भवन जर्जर व खतरनाक हो चुके हैं। ऐसे संस्थानों के भवनों का पुनर्विकास करना बहुत आवश्यक है। राज्य सरकार ने 1949 से 1969 और उसके बाद युद्धोत्तर पुनर्वास-219 योजना प्रारंभ की। इस योजना में पिछड़ा वर्ग सहकारी आवास समितियों को भूखण्ड आवंटित किये गये। इसके पीछे मंशा उन्हें मुंबई, पुणे, नासिक जैसे शहरी स्थानों में आश्रय देना और उन्हें पक्के और आरामदायक घर दिलाना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना था।

अब इस नई नीति के कारण ऐसे भवनों के पुनर्विकास संबंधी पूर्व सरकार के सभी निर्णय रद्द कर दिए गए हैं और नई नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे संगठनों में मूल सदस्यों की दृष्टि से पिछड़ा वर्ग का 90 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग का 10 प्रतिशत यथावत रहेगा, पुनर्विकास के बाद निर्मित अतिरिक्त आवासों में पिछड़ा वर्ग का अनुपात 20 प्रतिशत एवं पिछड़ा वर्ग का 80 प्रतिशत रहेगा।

मुंबई के 210 अवैध स्कूल बंद कराने की कवायद में जुटी बीएमसी

मुंबई : महानगर पालिका ने 210 अवैध स्कूलों को बंद कराने से जुड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और स्कूलों को नोटिस जारी कर कहा गया है कि वे सरकार से जरूरी मंजूरी लें या स्कूल बंद करें। प्रबंधन को चेतावनी दी गई है कि अगर स्कूल बंद नहीं किए गए, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रशासनिक कार्रवाई के साथ मनपा अधिकारियों ने अभिभावकों को भी कहा है कि वे अवैध स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला न कराएं। अवैध स्कूलों के बाहर पोस्टर! ज्यादातर स्कूल वहीं हैं, जो पिछले साल जारी की गई ढाई सौ से ज्यादा अवैध स्कूलों की सूची में मौजूद थे। यह सूची मुंबई महानगर पालिका की वेबसाइट पर मौजूद है। एक अधिकारी ने कहा कि हम अवैध स्कूलों के बाहर पोस्टर लगाने पर भी विचार कर रहे हैं, जिससे अभिभावक को स्कूल जाने पर पता चल जाए कि स्कूल अवैध हैं। बच्चों को वैध सरकारी स्कूलों में दाखिला अधिकारी के मुताबिक, अवैध स्कूलों से नाम निकालने के बाद सभी बच्चों को वैध सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे के पास है और उसे दाखिला देना प्रशासन की जिम्मेदारी है। बीएमसी ऐसे बच्चों को अपने स्कूलों में दाखिल करेगी। मुंबई के अवैध स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 35 हजार से ज्यादा है।

भांडुप में मानसून से पहले सड़कों पर जलभराव

कहीं पाइप टूटी तो कहीं नालियां बन रही मार्ग में बाधा

भांडुप : अगर आप एलबीएस रोड से भांडुप स्टेशन रोड की तरफ जा रहे हैं तो जरा सावधानी से यात्रा करिए क्योंकि आपको इस मार्ग पर टूटी सड़कें, बजबजाती नालियां और तो और सड़कों पर बहती नालियों का पानी आपके मार्ग में बाधक बनेंगे। स्टेशन रोड के एफओबी के समीप एक जगह तो पानी की पाइपलाइन भी विगत चार दिनों से फूटी है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा।

सुबह-सुबह ऑफिस, स्कूल के लिए जब लोग निकलते हैं तो वह सड़क को बड़ी सावधानी से पार कर रहे हैं, क्योंकि यह सड़क बारिश के दिनों की याद दिला रही हैं। लोगों को डर लगा रहता है कि इस मार्ग पर हुए जलजमाव से होकर गुजरते वाहनों के गंदे पानी के छींटें कहीं उनके कपड़े न खराब कर दें।

सड़क पर जमा हो रहा नाले का पानी

बताते हैं कि एलबीएस रोड पर इन दिनों मेट्रो का काम चल रहा है, जिसके चलते लोगों को जाम का सामना करना पड़ता हैं। इन सबके इतर भांडुप स्टेशन रोड के समीप कुछ दिनों से सुबह के समय सड़कों पर नाले का पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से इस मार्ग से आने-जाने वाले लोग बहुत ही बच-बचाकर अपने-अपने गंतव्यों को जा रहे हैं। इस मार्ग पर पैदल चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लोगों को अब ऐसा लगने लगा है मानो मानसून की झमाझम बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया हो। वहीं इस स्टेशन रोड पर कुकरेजा काम्प्लेक्स के सामने एक पाइपलाइन फूटी हुई है, जिस वजह से सड़क पर पानी बह रहा है। थोड़ी दूर पर ही एलबीएस रोड पर सड़क टूटी हुई हैं और महीनों से वहां पर कूड़ा जमा हुआ है, जिसके चलते नाली का पानी जमा हो रहा हैं।

शिवसेना-यूबीटी ने किया BJP पर वार

कहा- महाराष्ट्र में दंगों की प्रयोगशाला खोलने की कोशिश

मुंबई : महाराष्ट्र में बीते दिनों कई धार्मिक दंगे हुए हैं। इसको लेकर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने अपने मुखपत्र सामना में एक लेख के जरिए मुख्यमंत्री शिंदे और गृहमंत्री फडणवीस की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का दंगे भड़का कर राजनीतिक रोटियां सेंकने का धंधा पीढ़ियों से चला आ रहा है और चुनाव नजदीक आते ही इस धंधे के निवेश में बढ़ोतरी की जाती है।

राज्य के लोगों हों सतर्क

शिवसेना (उद्धव गुट) ने कहा कि राज्य के लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वे उन लोगों से घिरे हुए हैं, जो संविधान, राष्ट्रीय एकता और धार्मिक भावना को दरकिनार कर सत्ता पाने की लालसा रखते हैं। सामना में कहा कि राज्य की जनता को महाराष्ट्र के हित के लिए सावधान रहना होगा। महाराष्ट्र में दंगों की प्रयोगशाला खोलकर भाजपा और उसके समर्थक सामाजिक समरसता को बिगाड़कर मतों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं।

कई बार हो चुके हैं दंगे

महाराष्ट्र में पिछले शनिवार और रविवार को क्रमशः अकोला शहर और अहमदनगर जिले के शेवगांव गांव में सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 13 अन्य घायल हो गए थे। वहीं, अन्य घटना में एक अलग धर्म के सदस्यों ने कथित तौर पर नासिक जिले के प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश की, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।

संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

राज्यपालों के लिए मुश्किल

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिरने और शिंदे सरकार के गठित होने को लेकर राज्यपाल की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में जो कहा उसकी कानूनी स्थिति सभी पक्षों को स्वीकार करनी होगी। हालांकि, जो कानून के जानकार नहीं हैं उन्हें भी इसकी विवेचना और उसे व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी की इस मामले में भूमिका को आड़े हाथों लिया। कोश्यारी की यह आलोचना मेरी समझ से परे है। आखिर, जब राज्यपाल के पास सरकार के विरोध में इतनी बड़ी संख्या में विधायकों के हस्ताक्षरित पत्र प्रस्तुत किए गए तो इसका एकमात्र यही निष्कर्ष था कि सरकार अल्पमत में आ गई है। पूर्व के ऐसे अनेक उदाहरण राज्यपाल के संज्ञान में रहे होंगे, जिनमें सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। फिर भी, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकरे को विश्वासमत हासिल करने को कहा। यह अपने आप में एक तर्कसंगत निर्णय रहा। वहीं, मुख्यमंत्री ठाकरे ने सदन का सामना किए बिना ही त्यागपत्र दे दिया। इसका अर्थ था कि वह समझ चुके थे कि उनके नीचे से बहुमत की जमीन सरक गई है। ऐसी स्थिति में कोश्यारी का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के बहुचर्चित एसआर बोम्मई मामले के अनुरूप ही था। कर्नाटक की बोम्मई सरकार को 21 अप्रैल, 1989 को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत बर्खास्त कर राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तब कुछ विधायकों नें विद्रोह किया था, लेकिन राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का अवसर नहीं दिया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए भविष्य के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश दिए कि ऐसे प्रकरणों में सही निर्णय तक कैसे पहुंचा जाए। उसमें स्पष्ट किया गया कि किसी भी राज्य सरकार के लिए बहुमत सिद्ध कराने का केवल एक ही स्थान है और वह है विधानसभा का मंच। उक्त निर्णय में ऐसी कोई तकनीकी जटिलता नहीं थी, जिन्हें सामान्य नागरिक न समझ सके। ऐसे में यह एक पहेली बनकर रह गई है कि जब राज्यपाल के रूप में कोश्यारी उन्हीं निदेशों का पालन कर रहे थे तो उसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें कैसे गलत ठहराया। ऐसे में अब जब भी महाराष्ट्र सरीखी स्थितियां उत्पन्न होंगी तो किसी राज्यपाल के समक्ष यह निर्णय करना अत्यंत कठिन होगा कि वह बोम्मई प्रकरण के दिशानिर्देश मानें या कोश्यारी के लिए दी गई शीर्ष अदालत की नसीहत का ध्यान रखें। भारत में समय-समय पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल और केंद्र से इतर राजनीतिक दल वाली राज्य सरकार में राजनीतिक-वैचारिक एकरूपता संभव नहीं हो सकती। दिल्ली में उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच निरंतर कायम विवाद इसका एक बड़ा उदाहरण हैं। ऐसे में पारस्परिक वैचारिक आदान-प्रदान समस्याओं का समाधान निकालने में सहायक हो सकता है। विमर्श लोकतंत्र में सबसे प्रभावी उपकरण है जो किसी भी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम है। जब ऐसा नहीं होता तो समस्याएं और टकराव बढ़ने लगते हैं। विमर्श का अभाव कई अप्रिय स्थितियों को जन्म देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब बंगाल के राज्यपाल थे तो अक्सर यही देखने को मिलता था कि राज्य सरकार किसी न किसी प्रकार से उनके अपमान का प्रयास करती रहती थी।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

महाराष्ट्र में दंगे जैसा माहौल बनाया रहा है, इसे रोका जाना चाहिए - पाटील

मुंबई : महाराष्ट्र में अलग-अलग जगहों पर दंगे जैसा माहौल बनाया रहा है। यह चिंता का विषय है। इस घटना की गहन जांच करने के लिए गृह विभाग द्वारा कदम उठाए जाने की मांग राकांपा प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व जल संसाधन मंत्री जयंत पाटील ने की। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में जान-बूझकर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, तो इसे रोका जाना चाहिए। जयंत पाटील ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को भी इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में दोबारा ऐसी घटनाएं न हों। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महाविकास आघाड़ी में अभी तक कोई फॉमूर्ला तय नहीं हुआ है। सिर्फ भविष्य में क्या करना है, इस पर चर्चा चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी चुनाव में सीट बंटवारे पर पैष्ठसला लेने के लिए कमेटी में तीनों दलों में से प्रत्येक के लगभग दो-दो नेता काम करेंगे। इसके साथ ही अन्य सभी मित्र दलों को भी भरोसे में लिया जाएगा, ऐसा भी पाटील ने कहा।

सीबीआई की कार्रवाई के बाद पूर्व मंत्री नवाब मलिक द्वारा समीर वानखेड़े पर लगाए गए सभी आरोप सच होते जा रहे हैं। समीर वानखेड़े का समर्थन कर रही भाजपा को सीबीआई की कार्रवाई के बाद समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा तंज जयंत पाटील ने भाजपा पर कसा। शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी का निर्माण किया, इसलिए राकांपा को टारगेट करने का मन भाजपा ने बनाया है, ऐसा आरोप भी उन्होंने लगाया।

मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, इसलिए मुझे रात को शांति से नींद आती है। इस पृथ्वी पर मेरे नाम पर एक भी घर नहीं है। इसलिए मुझे ईडी जांच से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील ने कहा। नेरले (तालुका वालवा) स्थित विकास सोसाइटी की इमारत का उद्घाटन जयंत पाटील के हाथों किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सांगली का घर पिता राजाराम बापू पाटील के नाम पर था। उसके बाद घर माता जी के नाम पर हुआ। अब माता जी के बाद नाम बदलने का काम शुरू है। कासे गांव में थोड़ी-बहुत खेती की जमीन है, जिसका बंटवारा नहीं हुआ है। सार्वजनिक जीवन में प्रमाणिक तरीके से काम करने का जोर देते आ रहे हैं। सत्ता दल द्वारा विरोध में बोलने वालों को फंसाने का काम वर्तमान में शुरू होने के कारण ऐसी जांच से डरने का कोई कारण नहीं है, ऐसा जयंत पाटील ने कहा।

भीषण गर्मी में बिजली की कटौती शुरू

ठाणे : ठाणे जिले सहित पूरे महाराष्ट्र में आसमान से भीषण गर्मी बरस रही है। ठाणेकर इलेक्ट्रिकल उपकरणों का इस्तेमाल करके खुद को कूल रख रहे हैं, लेकिन अब जिले के कई क्षेत्रों में बिजली की कटौती शुरू हो गई है। बिजली कटौती की वजह से आम ठाणेकरों के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में ठाणेकरों के सामने खुद को कूल वैष्ठसे रखें, ये सवाल खड़ा हो गया है।

बता दें कि ठाणे सहित आस-पास के क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी कुछ और दिन लू का प्रकोप जारी रहेगा। बढ़ती गर्मी के कारण पंखे और एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बढ़ते उपयोग के कारण बिजली की मांग भी बढ़ी है। नतीजतन, महावितरण पर बिजली आपूर्ति का दबाव बढ़ गया है। इसलिए जिले के अंबरनाथ और बदलापुर शहरों में आधिकारिक रूप से लोड शेडिंग शुरू हो गई है। हालांकि, इन दोनों शहरों में आधिकारिक रूप से लोड शेडिंग शुरू हो गई है, लेकिन ठाणे, कल्याण-डोंबिवली और आस-पास के शहरों में अघोषित लोड शेडिंग की तस्वीर देखने को मिल रही है।

रात के वक्त बिजली की अधिक मांग होती है। रात के वक्त बिजली की आपूर्ति निरंतर होती रहे इसलिए दिन के समय में बिजली की कटौती की जा रही है। मोरीवली उपकेंद्र से आपूर्ति किए जानेवाले अंबरनाथ, बदलापुर शहर प्रभावित होंगे। पर्याप्त बिजली आपूर्ति न कर पाने की वजह से आम नागरिकों में महावितरण के प्रति गुस्सा है। महावितरण की ओर से बताया गया है कि यह निर्णय शुक्रवार से तापमान में गिरावट और मांग में कमी आने तक लागू रहेगा। वागले इस्टेट, पाचपाखड़ी, तीन हात नाका, नौपाड़ा, कोलशेत, मनोरमानगर, बालकुम, हरिनिवास, राम मारुति रोड, आनंदनगर सहित ठाणे के कई हिस्सों में दोपहर के समय आधे से पौने घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। इन क्षेत्रों में बाजार, कई बड़े प्रतिष्ठान, कंपनियों के कार्यालय और बैंक हैं। बार-बार बिजली कटने से उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है।

1 लाख 58 हजार से अधिक मिल मजदूर अपने अधिकार के आवास से वंचित

मुंबई : मिल मजदूरों को उनके हक का घर देने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गई समिति में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के विधायकों को स्थान नहीं दिया गया है। मिल मजदूरों के आवास के मुद्दे को लेकर शिवसेना के विधायक कई बार विधानसभा में आवाज उठा चुके हैं। सरकार ने सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों को स्थान देकर राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए कमेटी बनाई है, यह स्पष्ट हो गया है। इस बीच डेढ़ लाख से अधिक मिल मजदूर अब भी आवास की प्रतीक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। १९८२ में मिल मजदूरों की ऐतिहासिक हड़ताल के बाद मुंबई में ५८ मिलें बंद हो गई थीं। इन मिलों की खुली जगह और बाकी एफएसआई का एक-तिहाई हिस्सा महानगरपालिका को एक-तिहाई म्हाडा को और एक-तिहाई मिल मालिकों को देने का पैष्ठसला किया गया था। इन बंद पड़ी मिलों की जमीन पर म्हाडा के माध्यम से मकान बनाए गए और मिल मजदूरों के मकानों की लॉटरी निकाली गई। इन मकानों के लिए १ लाख ७४ हजार मिलकर्मियों व उनके वारिसों ने आवेदन किया था। इन मिल मजदूरों के घरों की २०१०, २०११ और २०१७ में लॉटरी निकाली गई थी। एमएमआरडीए की रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत मिल मजदूरों के १३ हजार ४५३ घरों और २ हजार ४१७ अतिरिक्त फ्लैटों की लॉटरी म्हाडा के माध्यम से निकाली गई थी। इसके बाद भी एक लाख ५८ हजार से अधिक मिल मजदूर अपने अधिकार के आवास से वंचित रह गए हैं। इस समिति में गिरगांव में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के विधायकों को स्थान नहीं दिया गया है। विधायक अजय चौधरी और सुनील शिंदे मिल मजदूरों के लिए आवास के मुद्दे को लेकर समय-समय पर विधानसभा में आवाज उठाते रहे हैं। शिवसेना विधायकों द्वारा मिल मजदूरों के मुद्दों को लगातार उठाया गया, फिर भी मिल मजदूरों के मुद्दों से अवगत विधायकों की समिति से उन्हें बाहर कर दिया गया।

महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने की कोशिश

परमबीर सिंह को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया - पटोले

मुंबई : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि भाजपा ने एक साजिश के तहत महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। इसके लिए मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया। पटोले ने कहा कि एंटीलिया विस्फोटक मामले की साजिश रचने के अलावा महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने के लिए तत्कालीन गृहमंत्री पर १०० करोड़ रुपए की वसूली का झूठा आरोप लगाया गया। इस साजिश में मदद के करने के लिए अब इनाम के तौर पर निलंबित पुलिस अधिकारी परमबीर सिंह को शिंदे-फडणवीस सरकार ने फिर से बहाल करने का पैष्ठसला किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस मदद के बदले ईडी सरकार ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना सिंह के निलंबन को रद्द कर उन्हें सेवा में लौटने में मदद की है। पटोले ने कहा कि कैट के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि मुंबई हाईकोर्ट ने सीबीआई को स्पष्ट आदेश दिया था कि वह परमबीर सिंह के खिलाफ जांच कर चार्जशीट दायर कर विभागीय जांच करें लेकिन शिंदे-फडणवीस सरकार ने ऐसा नहीं किया। परमबीर सिंह को निलंबित कर दिया गया था लेकिन उनके निलंबन की हर तीन महीने में समीक्षा की जानी थी और विस्तार की आवश्यकता थी। शिंदे-फडणवीस सरकार ने न तो परमबीर सिंह की विभागीय जांच कराई और न ही उनका निलंबन बढ़ाया। इसलिए कैट ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई में राज्य सरकार के रुख से परमबीर सिंह को राहत मिली। पटोले ने कहा कि जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था तो दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से हुई मुलाकात में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें परमबीर सिंह के भ्रष्टाचार की फाइल दी थी। उन्होंने कहा कि संबंधित की ओर से उस फाइल की कॉपी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी दी गई थी। इसके बाद परमबीर सिंह मुझसे मिलने आए। उस वक्त जब मैंने खुद उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे विभाग में ऐसे ही काम होता है। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को परमबीर सिंह के भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी थी लेकिन इसके बावजूद भाजपा सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई तो दूर साधारण जांच तक नहीं कराई।

10 वर्षों में वायु प्रदूषण मे 237 प्रतिशत इजाफा

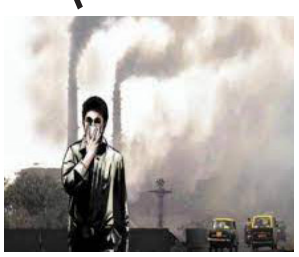

मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रदूषण दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यहां विकास के नाम पर बस नागरिकों को प्रदूषण परोसा जा रहा है। मेट्रो और बुलेट ट्रेन के नाम पर हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन शहर और नागरिकों के इस बुरे हालात का खयाल बीएमसी को नहीं है, जबकि मुंबई मे बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर लोगों ने मनपा से जमकर शिकायत की है। पिछले १० वर्षों में २३७ प्रतिशत इजाफा हुआ है। उधर कचरा के मामले में भी मुंबई में जमकर शिकायतें मिली हैं। आश्चर्य है कि झोपड़पट्टी इलाकों में कचरे कम निकले हैं, जबकि इमारतिया रहिवासी इलाकों में सबसे ज्यादा कचरे उठाए गए हैं। प्रजा फाउंडेशन ने मुंबई में जनता की समस्याओं की स्थिति पर रिपोर्ट-२०२३ जारी की है, जिसमें उन्होंने मुंबई में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों और नगरपालिका द्वारा इन शिकायतों को कम करने के उपाय के विषय में जानकारी दी है।

प्रजा फाउंडेशन ने अपनी रिपोर्ट मुंबई सीवरेज, हवा और पानी की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों में हुए इजाफों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है। मुंबई मे ठोस कचरे के निपटान से संबंधित नागरिकों की शिकायतों में १२४ प्रतिशत, जबकि वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायतों में २३७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रजा फाउंडेशन की जारी रिपोर्ट में मुंबई मे ठोस कचरे के निपटान से संबंधित जनता की शिकायतों में १२४ प्रतिशत, जबकि वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायतों में २३७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े वर्ष २०१३ की तुलना मे २०२२ में प्राप्त नागरिकों की शिकायतों पर आधारित हैं।

बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को यह प्रभावित कर रहा है स्मार्टफोन

मुंबई : आजकल हर घर में स्मार्ट फोन सामान्य बात हो गई है। बड़े तो बड़े अब तो बच्चों का भी निवाला बिना फोन हाथ में लिए उतरता ही नहीं। कमोबेश यही स्थिति हर घर की हो गई है। लेकिन इसका बुरा असर बच्चों के ऊपर कितना पड़ रहा है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, यह स्मार्टफोन बच्चों को मूर्ख बना रहा है। असल में कम उम्र के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को यह प्रभावित कर रहा है। उनके दिमाग पर स्मार्टफोन का बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

एक डॉक्टर के अनुसार, ६ साल के एक बच्चे ने अपना सिर जमीन पर पटक दिया था क्योंकि उसे फोन इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया गया। स्मार्टफोन का इस्तेमाल दिन-प्रतिदिन खतरनाक बनता जा रहा है। फोन का इस्तेमाल सिर्फ आपके मानसिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि आपको सामाजिक दुनिया से भी अलग कर कर रहा है।

हाल ही में 'सेपियन लैब्स' के एक नए वैश्विक अध्ययन में पाया गया है कि स्मार्टफोन के कम इस्तेमाल से बच्चों और युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। अध्ययन से पता चलता है कि वर्तमान १८-२४ वर्ष के युवाओं के बीच स्मार्टफोन बहुत प्रभाव डाल रहा है। इसमें महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करनेवाली युवा पीढी के मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही स्मार्टफोन तेजी से अपनाने वालों की सोशल हैबिट में भी बदलाव आया है।

मेरा निर्णय पूरी तरीके से निष्पक्ष होगा - विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक परंपरा को कायम रखते हुए निर्णय दिया है। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार को अबाधित रखते हुए उस पर मुहर लगाई है। अध्यक्ष पर जो जवाबदारी है, उसका पालन करते हुए मैं देर नहीं करूंगा। जल्द से जल्द निर्णय होगा। लेकिन ऐसा करते हुए मैं कोई जल्दबाजी भी नहीं करूंगा, ऐसा बयान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कल दिया। राज्य के सत्ता संघर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए निर्णय के विषय पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कल लगातार दूसरे दिन मीडिया से संवाद साधा।

उन्होंने कहा कि २०२२ जून-जुलाई में कौन सा राजनीतिक दल था, कौन से गुट का था? उसका निर्णय लेने के लिए कहा गया है। राजनीतिक पक्ष किसका था, यह निश्चित होने के बाद प्रतोद किसका होगा, गुट नेता कौन होगा? उसे मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद में सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। यहां याचिका में ५६ विधायकों को प्रतिवादी बनाया गया है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए प्राकृतिक न्याय प्रक्रिया से सुनवाई होगी। सुनवाई की पूरी प्रक्रिया करने के बाद निर्णय दिया जाएगा। हालांकि, अब तक मेरे पास कोई निवेदन नहीं आया है। ऐसा भी उन्होंने स्पष्ट किया है। उचित समय यह प्रत्येक केस के अनुसार होता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पक्ष कौन है यह तय करने के लिए आयोग को भी ३ महीने में है। न्यायालय में भी वक्त लगता है। मेरा निर्णय पूरी तरीके से निष्पक्ष होगा। मूल मुद्दा है कि राजनीतिक पक्ष किसका है। राजनीतिक पक्ष की इच्छा क्या थी, व्हिप कौन जारी करे? वर्ष २०२२ में कौन सा गुट राजनीतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यहां से निर्णय करना होगा। संसदीय पक्ष का नहीं, बल्कि राजनीतिक पक्ष का भी मत क्या था? इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। जैसा न्यायालय ने कहा है कि जुलाई में क्या परिस्थिति थी? उसका आकलन कर निर्णय अध्यक्ष को लेना है। ऐसा न्यायालय ने कहा है। उन्होंने कहा कि मैं किसी के दबाव के तहत काम नहीं करूंगा, न हीं कभी किया है। अध्यक्ष को धमकी देकर उसके मनमुताबिक निर्णय हो ऐसा किसी को लगता है तो यह उसकी गलतफहमी है।

मुंबई और गोवा के बीच वंदे भारत!

मुंबई : जहां एक तरफ रेलवे अपनी रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने व वंदे भारत ट्रेन चलाने के नाम पर मीडिया के जरिए वाहवाही लूट रही है, वहीं पहले से चल रही स्पेशल ट्रेनों की स्थिति भी दयनीय ही है। मुंबई और गोवा के बीच बहु प्रतीक्षित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परीक्षण १६ मई को हुआ। यह नई एक्सप्रेस सेवा जहां मुंबई में शुरू की जानेवाली चौथी वंदे भारत ट्रेन है, वहीं उस मार्ग पर चल रही तेजस एक्सप्रेस ट्रेन की एसी में खराबी होने के कारण स्थिति खराब रही।

मुंबई सेंट्रल और गांधीनगर को जोड़नेवाले वेस्टर्न रेलवे मार्ग पर शहर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई थी। उसके बाद मध्य रेलवे ने मुंबई-शिर्डी१ और मुंबई-सोलापुर मार्गों पर दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरूआत की। एक बार चालू होने के बाद ट्रेन यात्रा के समय को काफी कम कर देगी और यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ने की उम्मीद है।

18 महीने का टेंडर, आठ साल में भी नहीं बना नाट्यगृह

6 करोड़ 32 लाख 70 हजार 434 रुपये की लागत से तैयार होगा नाट्यगृह

नालासोपारा : वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत नालासोपारा पूर्व के अचोले में नागरिकों की सुविधाओ के लिए बन रहे मजेठीया नाट्यगृह निर्माण का कार्य मनपा की लापरवाही के चलते आठ वर्ष बाद भी अधर में लटका है।

वसई विरार मनपा द्वारा 2 करोड़ 82 लाख 70 हजार 470 रुपये की लागत से बन रह इस नाट्यगृह में इंटीरियर वर्क के लिए भी साढ़े तीन करोड़ रुपये का बजट मनपा ने पास किया है। कुल मिलाकर 6 करोड़ 32 लाख 70 हजार 434 रुपये की लागत से यह नाट्यगृह का निर्माण होना था। लेकिन आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी नाट्यगृह निर्माण का कार्य आज भी अधर में लटका हैं। वही नागरिकों द्वारा नाट्यगृह निर्माण को लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही है।

मॉनसून में मौसम की अपडेट जानकारी मोबाइल फोन पर मिलेगी

एसएमएस से किया जाएगा सतर्क

मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के निवासियों को मॉनसून के दौरान मौसम से जुड़ी अपडेट जानकारी उनके मोबाइल फोन पर मिलेगी। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने यह जानकारी दी। बीएमसी की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने मौसम की जानकारी देने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और उसके पास ऐसी प्रणाली है जिसके जरिए मौसम से जुड़ी जानकारी उसी समय दी जा सकती है।

चार जून तक आने की संभावना

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को कहा कि केरल के ऊपर दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरूआत में थोड़ी देरी हो सकती है और इसके चार जून तक आने की संभावना है। दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य रूप से लगभग 7 दिनों के मानक विचलन के साथ 1 जून को केरल में प्रवेश करता है। मौसम कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इस साल केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरूआत में थोड़ी देरी होने की संभावना है। केरल में मानसून की शुरूआत 4 जून को 4 दिनों की मॉडल त्रुटि के साथ होने की संभावना है। दक्षिणी राज्य में मानसून पिछले साल 29 मई, 2021 में 3 जून और 2020 में 1 जून को पहुंचा था। दक्षिण-पश्चिम मानसून का आगे बढ़ना केरल के ऊपर शुरूआत से चिह्नित है और गर्म और शुष्क मौसम से बरसात के मौसम में बदलने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। आईएमडी ने पिछले महीने कहा था कि अल नीनो की स्थिति के बावजूद भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में सामान्य बारिश होने की उम्मीद है।

एसएमएस के जरिए सतर्क किया जाएगा

बयान में कहा गया कि आपात स्थिति में नागरिकों को एसएमएस के जरिए सतर्क किया जाएगा। बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने विभिन्न एजेंसियों के साथ आपदा प्रबंधन और मॉनसून से जुड़ी तैयारियों को लेकर एक बैठक की। बयान के अनुसार चहल ने सभी विभागों और एजेंसियों को मॉनसून के दौरान पेश आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वय बढ़ाने को कहा है।

झुग्गी बस्ती में लगी आग, दो घायल

मुंबई : मुंबई के बांद्रा इलाके में बुधवार को तड़के एक झुग्गी बस्ती में आग लगने से दो लोग घायल हो गए। नगर निकाय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बांद्रा (पश्चिम) में नरगिस दत्त नगर स्थित झुग्गी बस्ती में तड़के चार बज कर करीब 40 मिनट पर लगी आग में किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। एक अधिकारी के मुताबिक, आग में भूतल और पहली मंजिल की 10-12 झोपड़ियां तबाह हो गईं। उन्होंने बताया कि दमकल की आठ गाड़ियों, पानी के सात टैंकर और कई अन्य अग्निशमन उपकरणों को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया गया और आग पर सुबह आठ बजे के आसपास काबू पा लिया गया। अधिकारी के अनुसार, घटना में दो लोग घायल हुए हैं, जिनकी उम्र 19 साल और 30 साल है।

'क्राइम ब्रांच-2' की टीम ने महिला सहित 3 चोरों को किया गिरफ्तार

वसई : एमबीवीवी पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत क्राइम ब्रांच 2 वसई युनिट की टीम ने एक ऐसी गुत्थी सुलझाई है। अपराध के घटित होने के 3 दिन के भीतर क्राइम ब्रांच 2 की टीम ने अपराध में अज्ञात आरोपियों के नामों का पता लगाकर उन्हें हिरासत में लेने तथा षड्यंत्र को सुलझाने में सफलता मिली है। उक्त गुत्थी को सुलझाने के लिए टीम ने तकरीबन 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला था। यह कार्रवाई डीसीपी (क्राइम) अविनाश अंबुरे व एसीपी अमोलमांडवे के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच 2 युनिट के पी.आई शाहूराज रणवरे, सपोनिरी सुहास कांबले व सपोनिरी सागर शिंदे की टीम ने की है। पुलिस ने बताया कि 9 मई 2023 शाम 5;30 बजे से 10 मई 2023 सुबह 10;25 के दरम्यान शिकायतकर्ता निकहत असगर खान (38) वसई प.स्थित के घर अज्ञात का चोर द्वारा ताला तोड़कर बेडरूम के कपाट के तिजोरी का लॉक तोड़कर 10 लाख 30हजार रुपये का आभूषण व नगदी चोरी करके फरार हो गया.

15 वर्षों से डकैती के 3 एवं मोक्का के एक मामले में वांछित आरोपी सातारा से गिरफ्तार

वसई: एमबीवीवी पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत मध्यवर्ती अपराध जांच शाखा की कार्रवाई में लगभग १५ वर्षों से डकैती के ०३ एवं मोक्का के ०१ मामलों में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह सफलता क्राइम डीसीपी अविनाश अंबुरे व एसीपी अमोल मांडवे के मार्गदर्शन में मध्यवर्ती अपराध जांच शाखा के पो.नि.राहुल राख की टीम ने पाई है।यह जानकारी पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को दी है। पुलिस ने बताया कि २१ अगस्त २००८ में काशिदकोपर फाटा,मांडवी,विरार या स्थान पर रेखा काशिनाथ चौधरी (४५) रहती है।वह एक रिहायशी मकान में सो रही थी,वहीं आरोपी टेचर बंडया काले और उसके साथियों ने आपस में सांठगांठ कर हाथ में लोहे की औजार लेकर,उसने शिकायतकर्ता के बंद दरवाजे को लात मारकर घर के दरवाजे के हैंडल व दरवाजे के हैंडल को तोड़ दिया और घर में घुस गया,शिकायतकर्ता व उसके पति को लोहे की रॉड से मारापीटा,उनके शरीर पर से १७,००० रुपये कीमती सोने के जेवरात जबरदस्ती छीन कर फरार हो गए थे,इस मामले में विरार थाने में आरोपी के ऊपर कलम ३९५, ३९७, ४५२, ३४२, मोक्का एक्ट के साथ धारा ३(१)(दो), ३(२), ३(४) के तहत केस दर्ज किया गया था।पुलिस ने बताया कि उक्त अपराध में वांछित आरोपी टेचर बंडया काले,निवासी-ललगुन,पुसेगांव, जिला सातारा,अपराध होने के बाद से सतारा नहीं मिला,वरिष्ठ ने अपराध में वांछित आरोपी की तलाश करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मार्गदर्शन और आदेश दिए थे।पुलिस के मुताबिक,गौरतलब है कि आरोपी टेचर बंडया काले और उसके साथीआपस में सांठगांठ कर विरार पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर लूट की कुल ३ वारदातों को अंजाम देकर फरार हो गए थे।लूट जैसे संगीन अपराध के आरोपी का अभीतक पता नहीं चल पाने के कारण पुलिस उपायुक्त (अपराध) अविनाश अंबुरे ने अपराध में मोस्ट वांटेड आरोपी को खोजन और गिरफ्तार करने की सलाह और मार्गदर्शन किया था।वरिष्ठों के निर्देश एवं मार्गदर्शन के अनुसार मध्यवर्ती अपराध शाखा को गुप्त मुखबिर के माध्यम से तथा तकनीकी विश्लेषण से प्राप्त सूचना के आधार पर उक्त आरोपी के बारे में सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी सतारा जिले में है,तदनुसार,मध्यवर्ती अपराध शाखा के अधिकारी और कर्मचारी सतारा गए और टेचर बंडया काले,निवासी-मु.पो. ललगुन,ता.पुसेगांव,जि. सातारा से पकड़ा और विरार पुलिस के हवाले कर दिया है।

बीएमसी की लापरवाही से डूबेगी मुंबई!

मीठी नदी के दौरे के बाद कांग्रेस नेता नसीम खान का आरोप

मुंबई: महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष नसीम खान ने मंगलवार को मीठी नदी और नालों में बारिश से हुई सफाई का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि बीएमसी की लापरवाही से मुंबई के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि पवई से माहिम खाड़ी तक अंदाजन 19 किलोमीटर तक मीठी नदी में जमा कीचड़ की सफाई की ही नहीं हुई है। इसी तरह, इस इलाके में कई बड़े नाले भी अब तक साफ नहीं हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल से इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि नालों की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहा है, लेकिन ठेकेदार और बीएमसी के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से यह सारा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। उन्होंने कहा कि 6 फीट गहरे नालों में जमा कीचड़ को सिर्फ 1 फीट तक ही साफ किया गया है, जबकि पांच फीट कीचड़ अब भी भरा हुआ है। इस तरह क्रांति नगर, बैल बाजार, सहार एयरपोर्ट की सुरक्षा दीवार के पास मीठी नदी से भी कीचड़ नीचे तक नहीं निकाला गया है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने इस वर्ष जून के पहले सप्ताह में मॉनसून आने की संभावना जताई गई है, बावजूद इसके मुंबई में धीमी गति से चल रहे काम, मीठी नदी और बड़े नालों की सही तरह से सफाई न होने के कारण इस वर्ष फिर मुंबई में जल-जमाव का खतरा पैदा हो गया है।

मालिक , मुद्रक,प्रकाशक ,संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस , गाला नं 3 - 4 ,अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ,सोनावला क्रॉस रोड नं 12 ,गोरगांव (पूर्व),मुंबई 63 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : 1 -ए, ग्राउंड फ्लोर साहिल मेंशन, बालमिया लेन, माहिम वेस्ट मुंबई 400016 मोबाइल नं 9987 77 5650 व्हाट्सप्प नं 7977 40 8589 : Email - editor@rokthoklekhaninews.com